मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य

बनाम

आलोक फयूल्स (पी) लिमिटेड निदेशक के माध्यम से

(2010 की सिविल अपील संख्या 8034)

15 सितम्बर 2010

अल्तमस कबीर और ए.के. पटनायक, जे.जे.

कोयला - कोयला वितरण - आवंटित कोयले का गलत उपयोग और कालाबाजारी - कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिसूचित कीमतों पर ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के माध्यम से उत्तरदाताओं जैसे विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की गई - उत्तरदाताओं ने कोल इंडिया की सहायक कंपनी बीसीसीएल के साथ एक एफएसए में प्रवेश किया था। - सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि उत्तरदाता एक आपराधिक साजिश में शामिल थे, जिसके कारण एफएसए के नियमों और शर्तों का उल्लंघन हुआ - यह आरोप लगाया गया कि एफएसए के तहत आवश्यक अपने संबंधित संयत्रों में आवंटित कोयले का उपयोग करने के बजाय उत्तरदाताओं ने खुले बाजार में उंची कीमतों पर बेच दिया, इसके बाद, बीसीसीएल ने उत्तरदाताओ को कोयले की आपूर्ति निलंबित कर दी -

उत्तरदाताओं ने कोयला आपूर्ति के निलंबन को चुनौति देते हुए रिट याचिकाएं दायर की - उच्च न्यायालय ने इस आधार पर उत्तरदाताओं को कोयला आपूर्ति फिर से शुरू करने का अंतरिम आदेश पारित किया कि कोई सामग्री नहीं है बीसीसीएल द्वारा यह दिखाने के लिए कि प्रतिवादी आवंटित कोयले की किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या गलत उपयोग में शामिल थे - का औचित्य - माना गया: उचित नहीं - उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि एफआईआर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी और इसलिए, एफआईआर में लगाए गए आरोपों के समर्थन में सामग्री सीबीआई के पास थी, न कि बीसीसीएल के पास - ऐसी सामग्री को अदालत के समक्ष नहीं रखा जा सका क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में सीबीआई को प्रतिवादी के रूप में षामिल नहीं किया गया था।- बीसीसीएल एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और यदि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर ने गंभीर संदेह पैदा किया है कि आवंटित कोयले को उत्तरदाताओं के संयंत्रों में उपयोग करने के बजाय खुले बाजार में बेचा जा सकता है, बीसीसीएल को उचित कार्यवाही में संदेह दूर होने तक उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति निलंबित करने का अधिकार था - उच्च न्यायालय के आदेश खारिज कर दिये गये। उच्च न्यायालय के आदेशें को रदद् किया गया भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत - धारा 120बी आर/डब्ल्यु एसएस

420, 467, 471- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - एस 13(2) आर/डब्ल्यु एस. 13(डी)

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिसूचित कीमतों पर ईंधन आपूर्ति समझौते(एफएसए) के माध्यम से उत्तरदाताओं जैसे विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की गई थी। उत्तरदाताओं ने कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी बीसीसीएल के साथ एक एफएसए में प्रवेश किया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की कि उत्तरदाता एक आपराधिक साजिश में शामिल थे जिसके कारण एफएसए की शर्तों का उल्लंघन हुआ। यह आरोप लगाया गया कि एफएसए के तहत आवश्यक अपने संबंधित संयत्रों में आवंटित कोयले का उपयोग करने के बजाय, उत्तरदाताओं ने उसे खुले बाजार में उच्च कीमतों पर बेच दिया। इसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड की सलाह पर बीसीसीएल ने उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति निलंबित कर दी।

व्यथित होकर उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर एफएसए के तहत उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति निलंबित करने वाले संचार को रदद् करने की प्रार्थना की और बीसीसीएल को कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू करने का निर्देश देने वाले अंतरिम आदेश के लिए भी प्रार्थना की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने बीसीसीएल द्वारा उत्तरदाताओं को आवंटित कोयले की किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या

गलत उपयोग किया जा रहा हो ऐसी कोई सामग्री नहीं होने के आधार पर प्रतिवादियों को कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू करने का निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच ने अंतरिम आदेश बरकरार रखा था।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए,

अभिनिर्धारित किया1.1 उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश और खंडपीठ का बीसीसीएल को प्रतिवादियों को कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू करने का निर्देश देना सही नहीं था। उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश और खंडपीठ इस बात को समझने में विफल रही कि आवंटित कोयले के गलत उपयोग और प्रतिवादियों द्वारा आवंटित कोयले को खुले बाजार में बेचने के आरोपों वाली एफआईआर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी और इसलिए आवंटित कोयले के गलत उपयोग या उत्तरदाताओं द्वारा खुले बाजार में कोयले की बिक्री के संबंध में जानकारी या सामग्री सीबीआई के पास थी न कि बीसीसीएल के पास। दरअसल, विशेश न्यायाधीश, सीबीआई मामलों की अदालत में जांच के बाद दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति मेंे सीबीआई अधिकारियों द्वारा प्रतिवादियों के संयंत्र परिसर में तलाशी ली गई थी। उत्तरदाताओं के संयंत्र गैर-कार्यात्मक पाये गये और उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार कर्मचारियों के नाम के साथ-साथ उत्तरदाताओं द्वारा उत्पादित तैयार माल की बिक्री से संबंधित अन्य

दस्तावेज नकली और पूर्ण विवरण के रूप में गढ़े गए पाये गये। ऐसे कर्मचारियों/कामगारों और तैयार माल के खरीददारों के संबंध में रिकार्ड में पते आदि प्रदान नहीं किये गये थे और इस प्रकार प्रतिवादी कंपनियों को जारी किए गए कोयले की मात्रा का उपयोग उनके संयंत्रों में नहीं किया गया था, बल्कि काले बाजार में बेच दिया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए आरोपों के समर्थन में सीबीआई के पास सामग्री थी कि वे अपने संयंत्रों में आवंटित कोयले का उपयोग नहीं कर रहे थे बल्कि उसे काले बाजार में बेच रहे थे, लेकिन इन सामग्रियों को अदालत के समक्ष नहीं रखा गया क्योंकि उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं में सीबीआई को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। (पैरा 13) (311-ई-एच) (312-ए-डी)

1.2 प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के जवाब में उच्च न्यायालय में दायर जवाबी हल्फनामे में, कोल इंडिया लिमिटेड और बीसीसीएल ने दलील दी है कि एफएसए के खंड 4.4 के तहत उत्तरदाताओं को उन्हें आवंटित कोयले की पूरी मात्रा का उपयोग करने की आवश्यकता थी। उनके द्वारा संयंत्रों में उपयोग करने के अलावा कोयले को किसी भी उदेश्य के लिए बेचने/स्थानांतरित नहीं करने का वचन दिया था और जैसा कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में एफएसए के इस खंड के उल्लंघन का खुलासा हुआ, कोल इंडिया लिमिटेड और बीसीसीएल को

उत्तरदाताओं द्वारा कोयले का आगे स्थानांतरण करने से रोकने के लिए आपूर्ति निलंबित करनी पड़ी। यह निर्णय उसके खंड 15 के संदर्भ में एफएसए की समाप्ति के संबंध में अंतिम निर्णय लंबित होने तक लिया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं का मामला यह था कि उत्तरदाताओं द्वारा कोयले के आगे के विचलन को रोकने के लिए कोयले की आपूर्ति को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड और बीसीसीएल भारत सरकार की सरकारी कंपनियां है और भारत सरकार कोयला मंत्रालय के नीतिगत निर्णयों से बंधी है और चूंकि नई कोयला ई वितरण नीति के तहत आवंटित कोयले का गलत उपयोग और ब्लेक-उत्तरदाताओं द्वारा ऐसे कोयले के विपणन की जांच की जानी थी। कोल इंडिया लिमिटेड और बीसीसीएल ने उत्तरदाताओं को एफएसए के तहत कोयले की आपूर्ति को निलंबित करने के लिए मनमाने ढ़ंग से या अनुचित तरीके से कार्य नहीं किया। यदि उन्होंने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर सीबीआई द्वारा किया गया गंभीर संदेह के आधार पर विचार किया हो तो सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि कोयले की आपूर्ति यदि उत्तरदाताओं को की जाती है तो उनके द्वारा इसका गलत उपयोग किया जा सकता है या खुले बाजार में बेचा जा सकता है। (पैरा 14) (312-ई-एच) (313-ए-सी)

1.3 एक प्रासंगिक विचार जिस पर सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड और बीसीसीएल को विचार करना होगा कि क्या उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति जारी रखने से गलत उपयोग नहीं हो सकता है या उत्तरदाताओं द्वारा कोयले की कालाबाजारी नहीं की जाएगी और एफआईआर में सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए एफएसए और सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। इस प्रासंगिक पहलू पर या तो उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश पारित करते समय या उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच ने एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश के खिलाफ एलपीए को खारिज करते समय विचार नहीं किया। (पैरा 15) (313-एफएच) (314-ए)

कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी बनाम् उतर प्रदेश राज्य (1991) 1 एससीसी 537 और स्टर्लिंग कम्प्युटर्स लिमिटेड बनाम् मैमर्स एम एंड एन पब्लिकेशन्स लिमिटेड एण्ड अदर्स (1993) 1 एससीसी 445 - संदर्भित।

अशका स्मोकलैस कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एण्ड अदर्स बनाम् भारत संघ एवं अन्य (2007) 2 एससीसी 640 - संदर्भित।

1.4 बीसीसीएल को प्रतिवादियों को कोयले की आपूर्ति निलंबित करने का अधिकार है, जहां उसे संदेह है कि उत्तरदाता आवंटित कोयले का गलत उपयोग कर सकते है और उसे खुले बाजार में बेच सकते हैं, क्योंकि, जैसा कि एफएसए और धारा 4.4 से स्पष्ट होगा कि नई कोयला वितरण नीति

में एफएसए का उददेश्य और सरकार की नीति उत्तरदाताओं को उनके संयंत्रों में उपयोग के लिए कोयला आवंटित करना है, न कि किसी अन्य उददेश्य के लिए। इसलिए यदि सीबीआई जो कि केन्द्र सरकार की प्रमुख जांच ऐजेंसी है द्वारा दर्ज की गई एफआईआर ने गंभीर संदेह पैदा किया है कि आवंटित कोयले को उत्तरदाताओं के संयंत्रों में उपयोग करने के बजाय खुले बाजार में बेचा जा सकता है। उचित कार्यवाही में संदेह दूर होने तक उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति निलंबित करना बीसीसीएल के अधिकार में है। (पैरा 16) (314-सी-एफ)

2010 के सीसी नंबर 5440, 5452 और 5459 से उत्पन्न विशेश अनुमति याचिकाएं दाखिल करने में हुई देरी को माफ किया जाता है।

2. अनुमति दी गई।

3. ये अपीलें झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2009 के डब्ल्यूपी (सी) नंबर 2948, 2009 के 3536 और 2009 के 3080 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06.10.2009 और अंतिम आदेश दिनांक 07.01.2010 के खिलाफ हैं। 2009 के एलपीए संख्या 484, 2009 के 485, 2009 के 486 और 2009 के 523 में झारखंड उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच की 2010। चूंकि मामलों के इस बैच में निर्णय के लिए तथ्य और कानून के सामान्य मुद्दे उठते हैं, इसलिए हम अपीलों का सामान्य निर्णय द्वारा निपटारा कर रहे हैं।

4. प्रासंगिक तथ्य बहुत संक्षेप में यह हैं कि उत्तरदाताओं को उनके संयंत्रों में धुआं रहित ईंधन के निर्माण में उपयोग के लिए विभिन्न मात्रा में कोयले की लिंकेज दी गई थी। 18.10.2007 को, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय ने पारंपरिक लिंकेज प्रणाली को बंद कर दिया और इसके स्थान पर एक नई कोयला वितरण नीति अपनाई जिसके तहत ईंधन आपूर्ति समझौते (संक्षेप में 'एफएसए') के माध्यम से विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की जानी थी। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तय और घोषित की जाने वाली अधिसूचित कीमतों पर। इस नई नीति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (संक्षेप में 'बीसीसीएल') ने कोयले की आपूर्ति के लिए उत्तरदाताओं के साथ एफएसए में प्रवेश किया। एफएसए के खंड 4.4 में प्रावधान है कि समझौते के तहत उत्तरदाताओं को आपूर्ति की गई कोयले की कुल मात्रा उत्तरदाताओं के संयंत्र में उपयोग के लिए है और उत्तरदाता किसी भी उद्देश्य के लिए कोयले को बेचेंगे या डायवर्ट या स्थानांतरित नहीं करेंगे और यदि वे इसमें शामिल होते हैं तो या ऐसे किसी भी पुनर्विक्रय या व्यापार में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो बीसीसीएल उत्तरदाताओं को देय किसी भी देनदारी या क्षति के बिना एफएसए को तुरंत समाप्त कर देगा। 07.06.2009 को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में 'सीबीआई') ने उत्तरदाताओं सहित 10 उपभोक्ताओं के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज

की, जिसमें आरोप लगाया गया कि 10 उपभोक्ताओं ने तत्कालीन श्री उदयन भट्टाचार्य के साथ आपराधिक साजिश रची थी। बीसीसीएल के महाप्रबंधक (एस एंड एम) ने 11,94,940 टन कोयला उठाया और अपने संबंधित संयंत्रों में इसका उपयोग करने के बजाय, इसे खुले बाजार में उच्च कीमतों पर बेच दिया और परिणामस्वरूप बीसीसीएल को लगभग 4,36,15,300/- रुपये का नुकसान उठाना पड़ा और आरोपियों ने स्वयं को गलत लाभ कमाया है। एफआईआर में, सीबीआई ने आगे कहा कि तथ्यों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 , 467 , 471 (संक्षेप में ' आईपीसी ') और धारा 13 (2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के कमीशन का खुलासा किया। श्री उदयन भट्टाचार्य और विभिन्न उपभोक्ता फर्मों के मालिकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (डी) और इसलिए, एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और जांच की जाए

इसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष ने बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को प्रतिवादियों सहित एफआईआर में नामित फर्मों को कोयले की आपूर्ति निलंबित करने की सलाह दी और तदनुसार बीसीसीएल ने 13 जून 2009 को एक वायरलेस संदेश द्वारा उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति निलंबित कर दी।

5. व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें एफएसए के तहत उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति को निलंबित करने वाले संचार को रद्द करने की प्रार्थना की गई और बीसीसीएल को कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू करने का निर्देश देने वाले अंतरिम आदेश के लिए भी प्रार्थना की गई। 06.10.2009 को, झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश पारित कर उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति इस आधार पर फिर से शुरू करने का निर्देश दिया कि बीसीसीएल द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी हुई थी। उत्तरदाताओं द्वारा किया गया या उनके द्वारा आवंटित कोयले का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग किया गया। अपीलकर्ताओं ने एलपीए में डिवीजन बेंच के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 06.10.2009 के अंतरिम आदेशों को चुनौती दी। आदेश दिनांक 07.01.2010 द्वारा डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ताओं को अंतरिम आदेशों को अपास्त करने के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ एलपीए को खारिज कर दिया, जैसे ही अपीलकर्ता उत्तरदाताओं के खिलाफ प्रतिकूल सामग्री प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और वैकल्पिक पारित आदेशों में एफएसए को समाप्त कर दिया गया।

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अनुपम लाल दास ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू करने का निर्देश देकर अंतरिम आदेशों द्वारा प्रतिवादियों को अंतिम राहत दी थी और यह कानून में स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू करने का निर्देश देने वाले अंतरिम आदेश को पारित करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया एकमात्र कारण यह था कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अलावा कोई सामग्री नहीं थी जो यह दिखाती हो कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी की गई थी या कोई उत्तरदाताओं द्वारा आवंटित कोयले का गलत उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि सीबीआई जैसी प्रमुख जांच एजेंसी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और एफआईआर से पहले उत्तरदाताओं का इतिहास उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति को निलंबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी मामले में एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जांच सीबीआई द्वारा पहले ही पूरी हो चुकी है और उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है जो अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए रुख की पुष्टि करता है कि उत्तरदाता अपने संयंत्रों के लिए कोयले का खुले बाजार में बिक्री के लिए उपयोग कर रहे थे।

7. श्री दास ने आगे कहा कि जिन दो उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति इसी तरह निलंबित कर दी गई थी, वे हैं मेसर्स सुशीला केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और मेसर्स मगध स्मोकलेस फ्यूल कंपनी ने दो अलग-अलग रिट याचिकाओं में पटना उच्च न्यायालय का रुख किया और पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 26.08.2009 को एक सामान्य आदेश पारित किया, जिसमें रिट याचिकाओं को इस निष्कर्ष के साथ अनुमति दी गई कि आपराधिक मामले की जांच या कोयले के दुरुपयोग का आरोप एफएसए के तहत कोयला आपूर्ति को निलंबित करने का कोई आधार नहीं है, लेकिन अपीलकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष एलपीए नंबर 2009 का 1265 और 2009 का 1266 दायर किया और डिवीजन बेंच ने इसे बड़े पैमाने पर माना। जनहित में कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू करने का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक अपीलकर्ता रिट याचिकाकर्ताओं के कारण बताओ पर विचार नहीं करते और योग्यता के आधार पर अंतिम निर्णय नहीं लेते। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसी तरह, कुछ अन्य उपभोक्ताओं, अर्थात् मेसर्स प्रताप फ्यूल इंडस्ट्रीज और मेसर्स नेशनल फ्यूल्स इंडस्ट्री ने कोयले की आपूर्ति के निलंबन के खिलाफ सिविल विविध रिट याचिका संख्या 33576/2009 और 36430/2009 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया। एफएसए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि

अपीलकर्ताओं द्वारा पारित दो उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति को निलंबित करने के आदेश में न्यायालय द्वारा अपने असाधारण क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसके बजाय अपीलकर्ताओं को स्पष्टीकरण पर विचार करने का निर्देश दिया । दो उपभोक्ताओं ने दिनांक 16.07.2008 को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और मामले में अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यद्यपि पटना उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उद्धृत किया गया था, लेकिन उन्हें खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों में संदर्भित या निपटाया नहीं गया था। एलपीए में झारखंड उच्च न्यायालय। उन्होंने कहा कि जिन 10 उपभोक्ताओं के खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है, उन्हें कोयले की आपूर्ति के संबंध में अब एक विसंगतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जो उपभोक्ता पटना उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय चले गए, उन्हें एफएसए के तहत कोयले की आपूर्ति नहीं मिल रही है, जबकि वे उपभोक्ता जो झारखंड उच्च न्यायालय चले गए और जिनके पक्ष में झारखंड उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है, वे कोयले की आपूर्ति के हकदार होंगे। एफएसए के तहत, हालांकि उपभोक्ताओं के दो वर्ग समान रूप से स्थित हैं।

8. श्री दास ने अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य [(2007) 2 एससीसी 640] पैरा 188 में

पृष्ठ 703 के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला दिया कि कोयले की कालाबाजारी और दुरुपयोग को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर उन्होंने कहा कि यह इस न्यायालय की इन टिप्पणियों के अनुसार है कि नई कोयला वितरण नीति लिंकेज सिस्टम को बंद करने के लिए बनाई गई है, जो कोयले की कालाबाजारी और खुले बाजार में कोयले की आपूर्ति और सख्त शर्तों पर कोयले की आपूर्ति के खतरे को नहीं रोक सकती है। और संयंत्रों में कोयले का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एफएसए में निर्धारित शर्तों पर विचार किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यही कारण है कि एफएसए के खंड 4.4 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि समझौते के तहत उत्तरदाताओं को आपूर्ति की गई कोयले की कुल मात्रा उत्तरदाताओं के संयंत्रों में उपयोग के लिए है और उत्तरदाता इसे बेचेंगे/डायवर्ट नहीं करेंगे और/या नहीं करेंगे। किसी भी उद्देश्य के लिए कोयला हस्तांतरित करना और यदि वे ऐसे किसी पुनर्विक्रय या व्यापार में संलग्न होते हैं या शामिल होने की योजना बनाते हैं, तो बीसीसीएल बिना किसी देनदारी और उत्तरदाताओं को देय किसी भी क्षति के एफएसए को तुरंत समाप्त कर देगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसलिए बीसीसीएल प्रतिवादियों को कोयले की आपूर्ति निलंबित कर सकती है यदि उत्तरदाता यह स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं कि उत्तरदाताओं को पहले से ही आपूर्ति किए गए कोयले का उपयोग उत्तरदाताओं के संयंत्रों में

किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एफएसए का खंड 13, जो यह प्रावधान करता है कि यदि उत्तरदाता कोयले की खरीद मूल्य के लिए बीसीसीएल को देय ब्याज सहित किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो बीसीसीएल उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति निलंबित कर सकता है, इसमें आकस्मिकताओं की संपूर्णता नहीं है। जिसे बीसीसीएल उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति निलंबित कर सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ ने विवादित आदेश पारित करते समय जनहित में किए गए एफएसए के इन प्रावधानों को नजरअंदाज कर दिया है।

9. प्रतिवादी मेसर्स आलोक फ्यूल्स (पी) लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एमएल वर्मा ने तर्क किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी का मामला यह था कि प्रतिवादी को कोयले की आपूर्ति मनमाने ढंग से और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में निलंबित कर दी गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी का उद्योग कार्यात्मक था जैसा कि 2008 की सिविल रिट याचिका संख्या 9863 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक की रिपोर्ट से स्पष्ट होगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी के खिलाफ सामग्री प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने के बावजूद विद्वान एकल न्यायाधीश या डिवीजन बेंच के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा

सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी को अब तक मिली सामग्री और सीबीआई द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप पत्र के साथ दायर की गई सामग्रियों को समझाने और खंडन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी मेसर्स फ़रीदाबाद इंडस्ट्रीज की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रणजीत कुमार ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच द्वारा पारित किए गए आदेशों का समर्थन किया और तर्क दिया कि इसके अलावा एफ.आई.आर. सीबीआई द्वारा दर्ज की गई, अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अन्य सामग्री नहीं रखी गई थी जो यह दिखाती हो कि उत्तरदाताओं मेसर्स फ़रीदाबाद इंडस्ट्रीज ने अपने संयंत्र से कोयले को हटा दिया और उसे खुले बाजार में बेच दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 15.07.2009 के आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं को उन सामग्रियों के बारे में उचित अवसर दिया गया था जो उस तारीख को उनके कब्जे में थीं जिस दिन आपूर्ति को निलंबित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन ऐसे अवसर के बावजूद, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह दर्शाने के लिए कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की कि प्रतिवादी मेसर्स फ़रीदाबाद इंडस्ट्रीज ने खुले बाज़ार में किसी भी तरह की कालाबाजारी या बिक्री का सहारा लिया है या अपने संयंत्र से

कोयला निकाला है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी मेसर्स फ़रीदाबाद इंडस्ट्रीज को कोयले की आपूर्ति उसके उद्योग और व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक थी और अदालत द्वारा प्रतिवादी के उद्योग को कोयले की आपूर्ति को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और इसलिए उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू करने का निर्देश देते हुए सही अंतरिम आदेश पारित किया था।

11. प्रतिवादी मेसर्स अजय एंड कंपनी फ्यूल प्रोडक्ट की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यूयू ललित ने श्री रणजीत कुमार की दलीलों को अपनाया और आगे प्रस्तुत किया कि यह उनकी ओर से दायर अतिरिक्त शपथ पत्र के पैरा 2 से स्पष्ट होगा। अपीलकर्ता ने 10.05.2010 को एसएलपी (सी) संख्या 11307 ऑफ 2010 में कहा कि 18.10.2007 से लागू नई कोयला वितरण नीति से पहले, 230 राष्ट्रीय उपभोक्ता और 94 कोकरी और कोकरी-सह-वॉशरी इकाइयां बीसीसीएल से कोयला ले रही थीं, लेकिन 18.10.2007 को इस नई नीति की शुरूआत के बाद, निजी कोकरी इकाइयों के अलावा केवल पांच उपभोक्ताओं को नई कोयला वितरण नीति के तहत एफएसए के निष्पादन के लिए उपयुक्त पाया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी मेसर्स अजय एंड कंपनी फ्यूल प्रोडक्ट एफएसए के निष्पादन के लिए उपयुक्त पाए गए इन पांच उपभोक्ताओं में से एक था और

इस स्तर पर अपीलकर्ताओं द्वारा यह स्टैंड नहीं लिया जा सकता है कि मेसर्स अजय एंड कंपनी फ्यूल प्रोडक्ट एफएसए के तहत कोयले की आपूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं था।

12. प्रतिवादी मेसर्स एमजीएम कॉनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एसबी उपाध्याय। लिमिटेड ने श्री रंजीत कुमार के तर्कों को अपनाया और आगे प्रस्तुत किया कि बीसीसीएल द्वारा मेसर्स के पक्ष में निष्पादित एफएसए का खंड 13। एमजीएम कॉनट्रेड प्रा. लिमिटेड ने शर्त लगाई कि यदि प्रतिवादी एफएसए के तहत बीसीसीएल को किसी भी ब्याज सहित किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो बीसीसीएल प्रतिवादी को कोयले की आपूर्ति निलंबित कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रतिवादी को कोयले की आपूर्ति एफएसए के तहत बीसीसीएल को देय किसी भी राशि या ब्याज का भुगतान करने में प्रतिवादी की ओर से विफलता के अलावा किसी भी आधार पर निलंबित नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसलिए, सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी को कोयले की आपूर्ति को निलंबित करना एफएसए के खंड 13 का उल्लंघन है। उन्होंने अशोका स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में पैरा 189 में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख किया कि इकाई की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए

कोयले की आपूर्ति के लिए किसी भी समझौते में प्रवेश करने से पहले निरीक्षण संबंधित कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए जिनके अधिकार क्षेत्र में इकाई स्थित है। श्री उपाध्याय के अनुसार, चूंकि ऐसे सभी निरीक्षण और जांच के बाद प्रतिवादी के पक्ष में एफएसए निष्पादित किया गया है, अपीलकर्ता इस स्तर पर यह रुख नहीं अपना सकते हैं कि प्रतिवादी की इकाई वास्तविक नहीं है।

13. हमने पार्टियों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और हमने पाया है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को एफएसए के तहत उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू करने का निर्देश देने का एकमात्र कारण यह है कि बीसीसीएल ने अदालत के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी है जिससे यह पता चले कि उत्तरदाताओं द्वारा कोयले की किसी भी प्रकार की कालाबाजारी की गई थी या उनके द्वारा आवंटित कोयले का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग किया गया था और यही कारण डिवीजन बेंच द्वारा भी दिया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एलपीए को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का आदेश। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ इस बात को समझने में विफल रहे कि आवंटित कोयले के गलत उपयोग और

प्रतिवादियों द्वारा आवंटित कोयले को खुले बाजार में बेचने के आरोपों वाली एफआईआर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी और इसलिए आवंटित कोयले के गलत उपयोग या प्रतिवादियों द्वारा खुले बाजार में कोयले की बिक्री के संबंध में जानकारी या सामग्री केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास थी, न कि बीसीसीएल के पास। तथ्य की बात यह है कि विशेश न्यायाधीश, सीबीआई मामले, धनबाद की अदालत में जांच के बाद जो आरोप पत्र दायर किया गया है, उसमें कहा गया है कि जून 2009 में सीबीआई अधिकारियों द्वारा प्रतिवादियों के संयंत्र परिसर में तलाशी ली गई थी। स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में, जिसके दौरान उत्तरदाताओं के संयंत्र गैर-कार्यात्मक पाए गए और उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार कर्मचारियों/श्रमिकों के नाम के साथ-साथ उत्तरदाताओं द्वारा उत्पादित तैयार माल की बिक्री से संबंधित अन्य दस्तावेज भी पाए गए। यह फर्जी और मनगढ़ंत है क्योंकि ऐसे कर्मचारियों/श्रमिकों और तैयार माल के खरीददारों के संबंध में रिकॉर्ड में पूर्ण विवरण, पते आदि उपलब्ध नहीं कराए गए थे और इस प्रकार प्रतिवादी-कंपनियों को जारी किए गए कोयले की मात्रा का उपयोग उनके संयंत्रों में नहीं किया गया था, बल्कि बेच दिया गया था। कालाबाजारी में. इस प्रकार यह स्पष्ट था कि प्रतिवादियों के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए आरोपों के समर्थन में सीबीआई के पास सामग्री थी कि वे अपने संयंत्रों में आवंटित कोयले का उपयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे काले बाजार में

बेच रहे थे, लेकिन इन सामग्रियों को अदालत के समक्ष नहीं रखा जा सका, क्योंकि उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं में सीबीआई को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

14. हम आगे पाते हैं कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं के जवाब में उच्च न्यायालय में दायर जवाबी हलफनामे में, कोल इंडिया लिमिटेड और बीसीसीएल ने दलील दी है कि एफएसए के खंड 4.4 के तहत उत्तरदाताओं को पूरी मात्रा का उपयोग करने की आवश्यकता थी। उन्हें अपने संबंधित संयंत्रों में कोयला आवंटित किया गया था और उन्होंने किसी भी उद्देश्य के लिए कोयले को बेचने/डायवर्ट/स्थानांतरित नहीं करने का वचन दिया था और जैसा कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में एफएसए के इस खंड के उल्लंघन का खुलासा हुआ, कोल इंडिया लिमिटेड और बीसीसीएल को आपूर्ति निलंबित करनी पड़ी। उत्तरदाताओं द्वारा कोयले के और अधिक विचलन को रोकने के लिए और यह निर्णय उसके खंड 15 के संदर्भ में एफएसए की समाप्ति के संबंध में अंतिम निर्णय लंबित होने तक लिया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं का मामला यह था कि उत्तरदाताओं द्वारा कोयले के आगे के विचलन को रोकने के लिए कोयले की आपूर्ति को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड और बीसीसीएल भारत सरकार की सरकारी कंपनियां हैं और भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के नीतिगत

निर्णयों से बंधी हैं, और चूंकि अशोका स्मोकलेस में इस न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार नई कोयला वितरण नीति तैयार की गई है। कोल इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य। (सुप्रा), आवंटित कोयले के गलत उपयोग और उत्तरदाताओं द्वारा ऐसे कोयले की कालाबाजारी की जाँच की जानी थी, कोल इंडिया लिमिटेड और बीसीसीएल ने उत्तरदाताओं को एफएसए के तहत कोयले की आपूर्ति को निलंबित करने के लिए मनमाने ढंग से या अनुचित तरीके से कार्य नहीं किया, यदि उन्होंने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर एक गंभीर संदेह व्यक्त किया कि कोयले की आपूर्ति, यदि उत्तरदाताओं को की जाती है, तो उत्तरदाताओं द्वारा इसका गलत उपयोग किया जा सकता है और खुले बाजार में बेचा जा सकता है।

15. यह कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी बनाम यूपी राज्य से शुरू होने वाले इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा तय किया गया है । [(1991) 1 एससीसी 537] कि संविदा संबंधी मामलों के क्षेत्र में भी, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर एक रिट याचिका पर विचार कर सकता है, जब राज्य या उसके साधन का विवादित कार्य मनमाना व तर्कहीन हो या अनुचित या सार्वजनिक कानून के तहत दायित्वों का उल्लंघन। स्टर्लिंग कंप्यूटर्स लिमिटेड बनाम मेसर्स एम एंड

एन पब्लिकेशंस लिमिटेड और अन्य [(1993) 1 एससीसी 445] में पैरा 28 में, हालांकि, इस न्यायालय ने कहा:

> "सार्वजनिक प्राधिकरण अनिवार्य रूप से निजी व्यक्तियों से भिन्न होते हैं। यहां तक कि वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में निर्णय लेते समय भी एक सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रासंगिक विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए न कि अप्रासंगिक विचारों से।"

जाहिर है, एक ऐसा प्रासंगिक विचार जिस पर सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड और बीसीसीएल को विचार करना होगा, वह यह है कि क्या उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति जारी रखने से उत्तरदाताओं द्वारा कोयले का गलत उपयोग या कालाबाजारी नहीं हो सकती है, जो कि प्रतिबंधित है। एफएसए और सरकार का नीतिगत निर्णय प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के आधार पर सीबीआई द्वारा एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर विचार करना है। इस प्रासंगिक पहलू पर या तो विद्वान एकल न्यायाधीश या उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित अंतरिम आदेश पारित करते समय या उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के आक्षेपित अंतरिम आदेशों के खिलाफ एलपीए को खारिज करते समय विचार नहीं किया गया है।

16. यह सत्य है जैसा कि उत्तरदाताओं की ओर से तर्क दिया गया है कि एफएसए के खंड 13(1) में यह प्रावधान है कि यदि उत्तरदाता 30 दिनों की अवधि के भीतर एफएसए के तहत बीसीसीएल को देय ब्याज सहित किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं। बकाया होने पर, बीसीसीएल को उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति निलंबित करने का अधिकार होगा, लेकिन खंड 13(1) यह निर्धारित नहीं करता है कि किसी अन्य आकस्मिक स्थिति में बीसीसीएल उत्तरदाताओं को एफएसए के तहत कोयले की आपूर्ति निलंबित नहीं कर सकता है। इसके अलावा, एफएसए का खंड 13(1) बीसीसीएल के लिए उपलब्ध तीन विकल्पों की गणना करता है, यदि कोयले की कीमत और ब्याज का बकाया उत्तरदाताओं द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है और यह विभिन्न आकस्मिकताओं के लिए प्रदान नहीं करता है जिसमें बीसीसीएल आपूर्ति को निलंबित कर सकता है। उत्तरदाताओं को कोयला. हमारी सुविचारित राय में बीसीसीएल को उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति निलंबित करने का भी अधिकार होगा, जहां उसे संदेह है कि उत्तरदाता आवंटित कोयले का गलत उपयोग कर सकते हैं और उसे खुले बाजार में बेच सकते हैं, क्योंकि, जैसा कि खंड 4.4 से स्पष्ट होगा। एफएसए और नई कोयला वितरण नीति निर्णय दिनांक 18.10.2007 के अनुसार, एफएसए का उद्देश्य और साथ ही सरकार की नीति उत्तरदाताओं को उनके संयंत्रों में उपयोग के लिए कोयला आवंटित

करना है, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। इसलिए, यदि केंद्र सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी, सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर ने गंभीर संदेह पैदा किया है कि आवंटित कोयले को उत्तरदाताओं के संयंत्रों में उपयोग करने के बजाय खुले बाजार में बेचा जा सकता है, तो उचित कार्यवाही में संदेह दूर होने तक उत्तरदाताओं को कोयले की आपूर्ति निलंबित करना बीसीसीएल के अधिकार में है।

17. हालाँकि, हमने पाया है कि बीसीसीएल ने उत्तरदाताओं को दिनांक 16.07.2009 को कारण बताओ नोटिस जारी करके ऐसी कार्यवाही शुरू की है, जिसमें यह बताया गया है कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर प्रतिवादियों के पक्ष में निष्पादित एफएसए को रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आरोप है कि उत्तरदाता एक आपराधिक साजिश में शामिल थे जिसके कारण एफएसए के नियमों और शर्तों का उल्लंघन हुआ। यदि उत्तरदाताओं ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, तो बीसीसीएल उस पर विचार कर सकता है और कानून के अनुसार कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू करने या नहीं करने का निर्णय ले सकता है।

18. इसलिए, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच ने बीसीसीएल को प्रतिवादियों को कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू करने का निर्देश देना सही नहीं था और तदनुसार दिनांक 06.10.2009 का आक्षेपित आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश और

दिनांक 07.01.2010 को की उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का आदेश अपास्त किया जाता है और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के इन अपीलों को स्वीकार करते हैं।

यह अनुवाद इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हेतराम मूंड, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकारणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारित उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।